भारत संघ एवं अन्य

बनाम

कैप्टेन सतेन्द्र कुमार

18 जुलाई, 2006

[अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंता, न्यायाधिपति]

सेवा कानूनः

सेना अधिनियम, 1950; धारा 19/सेना नियम; नियम 13-ए/रक्षा सेवा विनियम, पैरा 79:

सेना में कमीशन अधिकारी-पदोन्नति-दो चरणों में परीक्षा, भाग बी और भाग डी-तथ्यों को दबाकर भाग बी परीक्षा में अर्हता प्राप्त किए बिना भाग डी परीक्षा में उपस्थित होना-नोटिस-अधिकारियों ने त्रुटी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए उसे सेवा से सेवानिवृत्त करना-उच्च न्यायालय को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के सेना के निर्देशों में संशोधन को देखते हुए, अधिकारी सेवा में नियुक्ति का हकदार था-अपील पर, आयोजितःसंशोधन लागू होने तक, भाग बी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकारी के लिए उपलब्ध समय अवधि समाप्त हो

गई थी-केवल इसलिए कि संशोधन के बाद सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया था, परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए समय सीमा/शर्तों की प्रयोज्यता के रूप में स्थिति में बदलाव नहीं हुआ-इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश अक्षम्य था।

प्रतिवादी भारतीय सेना में एक कमीशन अधिकारी था। रक्षा सेवा विनियमों के पैरा 79 के साथ पढ़े गए सेना नियमों के नियम 13 - ए के अनुसार, सभी कमीशन अधिकारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार, गणना योग्य सेवा के 13 वर्षों के भीतर पदोन्नति परीक्षा (भाग बी) उत्तीर्ण करना आवश्यक था। इसके बाद, उन्हें सेवा के 20 वर्षों के भीतर पदोन्नति के लिए पार्ट डी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रतिवादी-अधिकारी पार्ट बी परीक्षा पूरी किए बिना पार्ट डी प्रमोशनल परीक्षा में शामिल हुआ था। चूंकि अधिकारियों ने उसे पार्ट डी परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य पाया, इसलिए उसका परिणाम रद्द घोषित कर दिया गया।

कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उसे नियमों के अनुसार. पार्ट डी परीक्षा के लिए गलत आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए उन्हें गंभीर नाराजगी (गैर रिकॉर्ड करने योग्य) से सम्मानित किया गया था। इस बीच, भारत सरकार ने सेना निर्देशों में संशोधन करते हुए पार्ट बी परीक्षा को पूरा करने की समय सीमा 13 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी।

अधिकारियों ने सेना अधिनियम, 1950 की धारा 19 के साथ पठित नियमों के नियम 13-ए के तहत उसे सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित किया क्योंकि वह असफल हो गया था।

निर्धारित समय अवधि के भीतर भाग बी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए। आदेश को चुनौती देते हुए, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया, तब तक संशोधित निर्देशों के अनुसार प्रमोशनल बी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि 13 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई थी, और इसलिए, प्रतिवादी पुनः प्राप्त करने का हकदार था। इसलिए, प्रतिवादी वर्तमान अपील में पुनः स्थापना का हकदार था।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि मूल रूप से निर्धारित 13 साल की अवधि समाप्त हो गई थी।

20 अगस्त 1999 को जारी किए गए संशोधित सेना निर्देशों में पार्ट बी प्रमोशनल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि 13 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई थी, जिसे 24.4.1998 से लागू किया गया था। जिस समय संशोधन लागू हुआ, प्रतिवादी-कमीशन अधिकारी को पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जो 13 वर्ष की अवधि उपलब्ध थी, वह समाप्त हो चुकी थी। जिसमें

सफलता न मिलने के संबंध में सूचना 11.9.1997 को प्रतिवादी को निर्धारित समय के भीतर परीक्षा भी दे दी गई थी। क्योंकि अंतिम आदेश 21.9.2001 को पारित किया गया था जिससे जहां तक प्रतिवादी का संबंध है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि 20 साल की विस्तारित अवधि प्रतिवादी पर लागू थी। [659 - डी - ई - एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 2084/2003

(सिविल विविध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 7.3.2002 के निर्णय और आदेश से रिट याचिका संख्या 37551/2001)

अमरेंद्र शरण, ए. एस. जी., रेखा पांडे, शिशी पिनाकी, सेलिनी रंजन

अपीलार्थियों की ओर से जी. फर्नांडिस और बी. वी. बलराम दास।

प्रत्यर्थी के लिए राकेश के. शर्मा (एन. पी.)।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिया गया निर्णय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी फिर से नियुक्त होने का

हकदार है और उसे भाग बी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 9.6.2004 तक का समय दिया जाना है।

संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रतिवादी को 9.6.1984 को भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सेना नियम, 1954 के नियम 13-ए के संदर्भ में (संक्षेप में रक्षा सेवा विनियम) के पैरा 79 के साथ पढ़े जाने वाले नियम (संक्षेप में सभी कमीशन अधिकारियों को विनियम पारित करने की आवश्यकता थी), मौजूदा नियमों के संदर्भ में पदोन्नति गणना योग्य सेवा के 13 वर्षों के भीतर परीक्षा (भाग बीइसके बाद, उन्हें 20 वर्षों के भीतर पदोन्नति के लिए भाग डी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से गलत और गलत प्रतिनिधित्व करते हुए कि उसने भाग बी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उत्तीर्ण हो गया है, आवेदन पत्र में भाग बी परीक्षा के परिणामों के बारे में सही विवरण दिए बिना अगली पदोन्नति भाग डी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। जब अधिकारियों ने पाया कि वह पात्र नहीं है, तो भाग डी परीक्षा में उसका परिणाम शून्य घोषित कर दिया गया। चूंकि प्रतिवादी ने मौजूदा नियमों और विशेष सेना निर्देशों के अनुसार भाग बी परीक्षा पूरी नहीं की थी, इसलिए नियमों के नियम 13-ए के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और

वैधानिक शिकायत की। जबकि मामला 8.1.1998 को लंबित था, प्रतिवादी को भाग डी परीक्षा के लिए गलत आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए गंभीर असुविधा (गैर-रिकॉर्ड करने योग्य) से सम्मानित किया गया था।

हालाँकि, यह नियम 13-ए के तहत पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से जुड़ा था। 20.8.1999 को भारत सरकार ने सेना निर्देशों में संशोधन किया जिसके तहत परीक्षा पूरी करने की समय सीमा 13 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई। हालाँकि इसे 24.4.1998 से लागू किया गया था। 5.7.2000 को अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को सेवा में नहीं बनाए रखने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया क्योंकि वह निर्धारित सीमा के भीतर भाग बी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में विफल रहा था। प्रश्नगत आदेश की प्राप्ति पर, जिसने प्रतिवादी को 15 दिनों के भीतर, यदि कोई हो, अभ्यावेदन देने की अनुमति दी, तो प्रतिवादी ने 2.8.2000 को अभ्यावेदन दिया। 21.9.2001 को सेना अधिनियम, 1950 की धारा 19 (संक्षेप में 'अधिनियम') के नियम 13 -ए के साथ पठित नियमों के अनुसार प्रतिवादी को सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित किया गया था।

प्रतिवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमे दिनांक 5.7.2000 के आदेश को चुनौती दी गयी थी। प्राथमिक रुख यह था कि जब आदेश पारित किया गया, तब तक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि 20 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी और इसलिए, उनके

पास प्रश्न में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 9.6.2004 तक का समय था। वर्तमान अपीलकर्ताओं ने बताया कि जब संशोधन किया गया तब तक सेना के निर्देशों के तहत निर्धारित 13 वर्षों की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी और किसी भी स्थिति में संशोधन 24.4.1998 से प्रभावी था और प्रतिवादी पर लागू नहीं था।

हालाँकि, उच्च न्यायालय का विचार था कि जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश सितंबर, 2001 में पारित किया गया था, तो इस अवधि को 13 वर्ष से संशोधित कर 20 वर्ष कर दिया गया था और इसलिए, प्रतिवादी पुनः नियुक्ति का हकदार था।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि हुई कि संशोधन प्रतिवादी पर लागू था। जिस समय संशोधन पेश किया गया था, उस समय मूल रूप से निर्धारित 13 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई थी, जहां तक प्रत्यर्थी का संबंध है और किसी भी स्थिति में संशोधन विशेष रूप से 24.4.1998 से प्रभावी बनाया गया था और स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के लिए लागू नहीं था। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं था।

हमें ऐसा प्रतीत होता हैं कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अस्थिर है।

प्रासंगिक नियम और निर्देश इस प्रकार है:

"पदोन्नति परीक्षा भाग बी (लेफ्टिनेंट से कैप्टन) एस. ए. आई. 1/एस/85 के अनुसार एस. ए. आई./26/एस/89 द्वारा संशोधित किया गयाः

15 (ए) पदोन्नति परीक्षा भाग बी. अधिकारी जो योग्यता प्राप्त करने में विफल रहते हैं पदोन्नति परीक्षा भाग बी 13 वर्ष पूरे होने तक मान्य 31 जुलाई 1984 से पहले कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए सेवा और 11 वर्ष या उसके बाद नियुक्त किए गए अधिकारियों के मामले में गणना योग्य सेवा 31 जुलाई, 1984 को ए. आर. 13-ए के तहत कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जाएगा। इन अधिकारियों की सेवा सेना नियम 13-ए में निहित प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दी जाएगी।

नियम 13 - ए: किसी परीक्षा या पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने में विफलता पर केंद्र सरकार द्वारा किसी अधिकारी की सेवा समाप्त करना :

(1) जब कोई अधिकारी उपस्थित नहीं होता है या उपस्थित होने के बाद प्रतिधारण परीक्षा या पदोन्नति परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है। उस परीक्षा या पाठ्यक्रम के संबंध में निर्दिष्ट समय या

विस्तारित समय के भीतर अन्य बुनियादी पाठ्यक्रम या परीक्षा, सेनाध्यक्ष (या सैन्य सचिव) अधिकारी से कारण बताने के लिए बुलाएगा कि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या सेवा से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।

(2) सेनाध्यक्ष (या सैन्य सचिव) द्वारा स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानने की स्थिति में, अधिकारी के स्पष्टीकरण और प्रमुख की सिफारिशों के साथ मामले को आदेश के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। सेना स्टाफ (या सैन्य सचिव) का अधिकारी होना चाहिए या नहीं:

(ए) सेवानिवृत्त होने के लिए बुलाया गया; या

(ख) त्यागपत्र देने का आह्वान किया।

(3) केंद्र सरकार, स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, अधिकारी और सेना प्रमुख की सिफारिश (या सैन्य सचिव), अधिकारी को सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, और ऐसा करने से इनकार करने पर, अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है या पेंशन या ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, पर सेवा से हटा दिया जा सकता है।"

जहां तक सेना निर्देशों और विनियमों में संशोधन का सवाल है, 20 अगस्त 1999 को जारी संशोधित सेना निर्देश 24.4.1998 से लागू थे। 20 अगस्त, 1999 को जारी संशोधित निर्देशों में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी।

संशोधन 24.4.1998 से प्रभावी होगा। जब तक संशोधन प्रभावी हुआ, तब तक प्रतिवादी को 13 वर्ष की अवधि बीतने के लिए उपलब्ध थी। पार्ट बी की परीक्षा समाप्त हो गयी. निर्धारित समय के भीतर परीक्षा में सफल न होने के संबंध में प्रतिवादी को दिनांक 11.9.1997 को नोटिस भी दिया गया था। केवल इसलिए कि अंतिम आदेश 21.9.2001 को पारित किया गया था कि जहां तक प्रतिवादी का संबंध है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट रूप से त्रुटी की है, कि वर्षों की विस्तारित अवधि प्रतिवादी पर लागू थी। उच्च न्यायालय का आदेश बचाव योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है. कोई लागत नहीं।

एस. के. एस.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।